



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2003/श्रावण 14, 1925

No. 705]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2003/SRAVANA 14, 1925

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2003

का.आ. 904(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित मामलों के संबंध में प्रमुख पतनों के प्रबंधन और उनके कर्मकारों, जिनका पत्तन एवं गोदी कर्मकारों के पांच मजदूर परिसंघ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, के बीच एक औद्योगिक विवाद मौजूद है और यह विवाद राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा है और इसकी प्रकृति भी ऐसी है कि एक राज्य से अधिक में स्थित प्रमुख पतनों की रुचि इस विवाद में हो सकती है या इस विवाद से उनके प्रभावित होने की संभावना है;

और जबकि, इस विवाद से जुड़े पक्षों ने संयुक्त रूप से इसके साथ संलग्न अनुसूची के उल्लिखित विवाद को न्याय निर्णयन हेतु राष्ट्रीय अधिकरण में भेजे जाने का आवेदन किया है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त विवाद का न्याय निर्णयन एक राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का गठन करती है जिसका मुख्यालय मुंबई में होगा और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम-न्यायालय, (सं. 1), मुंबई के पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति एस. सी. पाण्डेय को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण निर्दिष्ट करती है।

उक्त अधिकरण 6 माह की अवधि में अपना पंचाट दे देगा।

अनुसूची

“क्या दिनांक 8-2-1996 के समझौते तथा दिनांक 8 अक्टूबर, 2002 के समझौता ज्ञापन को देखते हुए सरकारी नियंत्रण के अधीन सेवा उद्योगों में कार्यरत कर्मकारों से संबंधित मौजूदा पी एल आर/पी एल आई स्कीम के दृष्टिगत सभी प्रमुख पतनों के संयुक्त औसत कार्य निष्पादन के आधार पर पत्तन और गोदी कर्मकारों को पी एल आर की अदायगी जारी रखे जाने के संबंध में परिसंघों की मांग न्यायोचित है अथवा प्रबंधन की मांग के अनुसार कर्मकारों के लिए पी एल आर की गणना तथा भुगतान, उनके संबंधित पतनों जिनमें वे नियोजित हैं, में कार्य निष्पादन के आधार पर किया जाना चाहिए।

दोनों ही स्थिति में कौन से पैरामीटर एवं फार्मूले अंगीकार किये जाने चाहिए?”

[फा. सं. एल-39011/6/2002 आई आर (एम)]

जे. पी. पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR**ORDER**

New Delhi, the 4th August, 2003

S.O. 904(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the management of Major Ports and their workmen represented by five Labour Federations of Port and Dock Workers in respect of the matters prescribed in the Schedule hereto annexed and that the dispute involves question of national importance and also is of such nature that Major Ports situated in more than one State are likely to be interested in or affected by such dispute;

And Whereas the parties to the dispute have applied jointly for a reference of the dispute mentioned in the schedule annexed below for adjudication by a National Tribunal;

And Whereas the Central Government is of the opinion that the said dispute should be adjudicated by a National Tribunal;

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 7B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) hereby constitutes a National Industrial Tribunal with headquarters at Mumbai and appoints Justice S. C. Pandey, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, (No. I), Mumbai as the Presiding Officer and in exercise of the powers conferred by Sub-section (I-A) of Section 10 of the said Act hereby refers the said industrial dispute to the National Industrial Tribunal.

The said Tribunal shall give its award within a period of six months.

SCHEDULE

“Having regard to the settlement dated 8-2-1996 and the Memorandum of Settlement dated 8th October, 2002, whether the Federations of Port and Dock Workers are justified in demanding that in view of the prevailing PLR/PLI Scheme for the workers employed in the service industries under Government control, the PLR should continue to be paid to the Port and Dock Workers on the basis of combined average performance of all the Major Ports or whether as demanded by the management, PLR should be calculated and paid to workers on the basis of performance of the respective ports in which they are employed?

In either case what should be the parameters and formulae to be adopted ?”

[F. No. L-39011/6/2002-IR(M)]

J.P. PATI, Jt. Secy.